

कार्यकारी सार

वर्तमान में, तीन नियंत्रित उत्पाद, अर्थात् हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), सार्वजनिक संवितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए बेहतर मिट्टी का तेल (एसकेओ) और घरेलू उपयोग के लिए द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) हैं। मोटर स्पिरिट (एमएस) या पेट्रोल को जून 2010 से विनियंत्रित कर दिया गया है। 2007-12 की अवधि को कवर करने वाले मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा पणधारियों-अर्थात् ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों (ओएमसीज), अन्त उपभोक्ताओं, सरकार और अपस्ट्रीम कम्पनियों पर इसके प्रभाव को अभिनिश्चित करने के लिए नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण कार्यप्रणाली के संदर्भ में की गई थी। महत्वपूर्ण

ओएमसी पर मूल्य निर्धारण का प्रभाव

अन्त उपभोक्ताओं पर मूल्य निर्धारण का प्रभाव

सरकार और अपस्ट्रीम कम्पनियों पर मूल्य निर्धारण प्रभाव

लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- ❖ रिफाइनरी गेट कीमत (आरजीपी) अपनी एफओबी (पोत पर्यन्त निः शुल्क) कीमत पर उत्पादों के आयात सहित सम्बद्ध विभिन्न लागत घटकों को जोड़ते हुए निकाली गई है, यद्यपि यह कच्चा माल या कच्चा तेल (और उत्पाद नहीं हैं) जिसे रिफाइनरियों द्वारा आयात किया गया है। ओएमसीज इन खर्चों का अधिकांश वहन नहीं करती हैं क्योंकि इन उत्पादों में से अधिकांश को आयात करने की बजाय ओएमसी रिफाइनरियों में संशोधित किया जाता है। वित्तीय शर्तों में 2007-12 के दौरान एफओबी कीमत के रिफाइनरियों में उत्पादित नियंत्रित उत्पादों पर रिफाइनरी गेट पर प्रभारित आयात संबंधी घटकों की गणना ₹ 50,513 करोड़ की गई थी। कच्चे तेल के आयात पर जो उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 23,887 करोड़ पर अनुमानित था, के आयात संबंधी व्ययों की अनुमति के बाद ओएमसीज कीमत लाभ व्युत्पन्न करने की अपेक्षा करेगी। तथापि, यह लाभ शोधन मार्जिन, उत्पादन की लागत के इष्टतम उपयोग और उत्पादों में सुधारों में प्रभावी वृद्धि के संबंध में पर्याप्त रूप से परिवर्तित होता हुआ प्रतीत

नहीं होता। यह अधिकतर पीएसयू रिफाइनरियों की अंतर्निहित समस्याओं, अर्थात् पुरानी अलाभकारी आकार, समाकृति के सीमाओं आदि के कारण हैं।

(पैरा 3.1.1 एवं 3.1.2)

- ❖ ओएमसीज ने विद्यमान पुरानी रिफाइनरियों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के प्रति कुछ कदम उठाए हैं। तथापि, विशेष रूप से आईओसीएल की हल्दिया रिफाइनरी और बीपीसीएल और एचपीसीएल की मुम्बई रिफाइनरियों में अभी सुधार की गुंजाइश है।

(पैरा 3.1.3)

- ❖ ओएमसीज ने आरजीपी (अर्थात् एमएस और एचएसडी के लिए व्यापार समता कीमत या टीटीपी और दूसरे उत्पादों के लिए आयात समता कीमत या आईपीपी) पर उत्पादन और घरेलू आवश्यकता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए एकमात्र/निजी रिफाइनरियों से पेट्रोलियम उत्पादों को उठाया था। निजी शोधकों ने ईपीपी/एफओबी की तुलनीय कीमतों पर, जोकि टीपीपी/आईपीपी से कम हैं, शेष पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। टीपीपी/आईपीपी की खरीद निजी शोधकों को अनुचित लाभ पहुंचाती है (रिलायंस इन्डस्ट्रीज लि. और एस्सार ऑयल लि.) जोकि केवल एक वर्ष अर्थात् 2011-12 में एचएसडी पर ₹ 667 करोड़ अनुमानित किया गया था। समान कारण पर एकमात्र पीएसयू रिफाइनरियों के लिए लाभ 2011-12 के दौरान ₹ 1,428 करोड़ था।

(पैरा 3.1.4)

- ❖ वास्तविक परिवहन लागत और मालभाड़ा के कारण उत्पाद के मूल्य निर्धारण में दर्शाई गई राशियां बेमेल हैं। ओएमसीज को वास्तविक लागत में थोड़ा अधिक क्षतिपूर्ति की गई थी, संगणित क्षतिपूर्ति परिवहन के विभिन्न माध्यमों पर (और परिवहन के वास्तविक माध्यम से नहीं) और पाइपलाइनों की परिचालन लागत पर हुए वास्तविक लागत के आधार पर थी।

(पैरा 3.1.6)

- ❖ ओएमसीज ने सभी वर्षों में सरकार द्वारा निर्धारित अनुज्ञेय दर पर नियंत्रित उत्पादों की बिक्री पर अधिक विपणन लागत वहन की। जबकि, आईओसीएल और बीपीसीएल नियंत्रित उत्पादों पर निर्धारित विपणन मार्जिन पर कुछ बेशी को सृजित कर सका है इसलिए एचपीसीएल वांछित विवरणी को सृजित नहीं कर

सका । इसी प्रकार, खुदरा निवेश पर मार्जिन बीपीसीएल और एचपीसीएल में वांछित स्तर से कम था।

(पैरा 3.1.7)

- ❖ कम वसूली दावों के विलम्बित निपटान के संदर्भ में कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओएमसीज ने ₹ 3,994 करोड़ की हानि वहन करते हुए सरकार द्वारा जारी ऑयल बॉण्ड को सस्ते दाम पर बेच दिया था। ओएमसीज ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान उधार ली गई कार्यचालन पूंजी पर ब्याज के प्रति ₹ 22,802 करोड़ का भी व्यय किया और क्षतिपूर्ति देने में विलम्ब के कारण ₹ 5,180 करोड़ की ब्याज हानि का वहन किया। नकद क्षतिपूर्ति की घोषणा में विलम्ब के कारण भी ओएमसीज द्वारा अग्रिम आयकर के कम भुगतान पर ₹ 381 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

(पैरा 3.1.10)

- ❖ जबकि केंद्रीय करों का आवधिक रूप से पुनर्गठन किया गया, फिर भी राज्य कर व्यापक रूप से और यथा मूल्य दरों से भिन्न हैं जिसके कारण बढ़ती उत्पाद कीमतों के साथ ग्राहकों पर अधिक भार पड़ा है। विशेष करों की ओर पारगमन सहित राज्य करों का अभी पुनर्गठन किया जाना है।

(पैरा 3.2.2)

- ❖ ओएमसीज, अपस्ट्रीम कम्पनियों और सरकारी नामक पणधारकों के मध्य कम वसूलियों के शेयरिंग की कोई एक समान प्रणाली नहीं थीं जिसके कारण अपस्ट्रीम कम्पनियों और ओएमसीज दोनों के लिए अनिश्चितता हुई।

(पैरा 3.3.1)

- ❖ सुपात्र उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक सहायता का लक्ष्य बनाने के लिए तंत्र के कार्यान्वयन में विलम्ब से कम वसूलियों में वृद्धि हुई। यद्यपि आर्थिक सहायता युक्त एलपीजी सिलेंडरों के लिए पात्रता बढ़ा दी गई और एलपीजी सिलेंडरों के लिए लाभ के सीधे हस्तांतरण के लिए योजना शुरू की गई है, पीडीएस मिट्टी के तेल की आपूर्तियों के लक्ष्य पर अधिक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी थी।

(पैरा 3.3.2)

- ❖ सरकार ने गैर-आर्थिक सहायता प्राप्त बाजार अवधारित कीमत का भुगतान करने वाले एचएसडी के थोक उपभोक्ताओं के साथ जनवरी 2013 में एचएसडी पर दोहरी कीमत निर्धारण नीति कार्यान्वित की। इस परिवर्तन के बाद खुदरा

एचएसडी बिक्रियों में वृद्धि हुई है, और कुल एचएसडी बिक्री में थोक एचएसडी के हिस्से में 2011-12 के दौरान 18 प्रतिशत के वार्षिक औसत के प्रति अगस्त 2013 में लगभग 10 प्रतिशत तक गिरावट हुई। सस्ते आर्थिक सहायता युक्त ईंधन के संभावित विचलन को रोकने के लिए उपयुक्त जांच की आवश्यकता है जो कम वसूलियों पर थोक ग्राहकों के लिए बाजार के मूल्य निर्धारण से सकारात्मक प्रभाव को कम करेगा।

(पैरा 3.3.3)